भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2405

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रीन सर्टिफाइड भवनों और सौर ऊर्जा चालित अवसंरचना का विकास

2405. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी ओडिशा में ग्रीन सर्टिफाइड भवनों और सौर ऊर्जा में चलने वाली अवसंरचना के विकास के लिए प्रोत्साहन शुरू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ओडिशा में ऊर्जा की कम खपत करने वाली आवासीय और सार्वजनिक अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार की बलांगीर और सोनपुर के सरकारी भवनों के लिए सोलर रूफटॉप योजनाओं का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ओडिशा में शहरी निवासियों में ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी नियोजन का कार्य शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों का है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करने में मदद करता है। सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf) पर जारी किए हैं।

यूआरडीपीएफआई दिशा-निर्देश 2014 के अध्याय 6 "सतत दिशा-निर्देश" के पैरा 6.1.2 ऊर्जा दक्षता में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के आधार पर भवनों के ऊर्जा कुशल डिजाइन के विकास का वर्णन है, जो ऊर्जा कुशल भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा प्रदर्शन मानक प्रदान करता है। यह गैर-पारंपरिक ऊर्जा/नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग तथा हरित भवनों को बढ़ावा देने की भी सिफारिश करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अध्याय 10 "हरित भवन और स्थिरता" के पैरा 10.2.5 सतत अपशिष्ट प्रबंधन और 10.2.6 आदर्श भवन निर्माण उप-नियम (एमबीबीएल) 2016 के निर्माण सामग्री की स्थिरता में भू-जलवायु स्थितियों के आधार पर सतत पर्यावरण के अनुकूल और स्थानीय भवन निर्माण सामग्री के उपयोग की सिफारिश की गई है।

सरकार ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना शुरू की। इसके एक घटक में सरकारी भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा लगाना शामिल है। 03.07.2024 को जारी किए गए संचालन दिशा-निर्देशों में इस योजना के तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारी भवनों की सेच्यूरेशन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं को रेखांकित किया गया है। इस घटक का मुख्य उद्देश्य ओडिशा राज्य के बालंगीर और सोनपुर सहित सभी सरकारी भवनों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर परिपूर्ण करना है। सरकारी क्षेत्र में भवनों के लिए इस योजना के तहत कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) सभी केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है, ताकि सरकारी भवनों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर उन्हें परिपूर्ण किया जा सके।

विद्युत मंत्रालय ने सूचना दी है कि ओडिशा की राज्य नामित एजेंसी (एसडीए) ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) भुवनेश्वर और ओडिशा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय (ओयूटीआर), भुवनेश्वर के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। एसडीए ओडिशा ने ओडिशा में 31 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से ऊर्जा कुशल कृषि पंप सेटों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए पंप तकनीशियनों और किसानों के लिए 31 जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 109 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शामिल करते हुए लगभग 2.3 लाख स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी

लाइट लगा दी गई है। इसके अलावा, पुरी में 10 सीवरेज शोधन संयंत्रों में निवेश ग्रेड ऊर्जा आडिट का कार्य पूरा हो गया है। नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन के अन्तर्गत एसडीए ओडिशा यूटिलिटी सेवाओं जैसे स्ट्रीट लाइट, वॉटर पंपिंग, सीवेज शोधन संयंत्र आदि के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

*****